विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां को दिल्ली नगर निगम को सौंपना

६६. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की किन-किन बस्तियों को दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है ;

(ख) शेष बस्तियां कब तक हस्तांतरित कर दी जायेंगी ;

(ग) कौन कौन सी बस्तियां अभी तक दिल्ली नगर निगम को नहीं सौंपी गई हैं ;

(घ) यह हस्तांतरण किस करार के आधार पर किया गया है ;

(ङ) इन बस्तियों के लिये सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितनी राशि दी है ; और

(च) इन बस्तियों में किये गये विकास कार्य का ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित की गई विविध शरणार्थी बस्तियों की सेवाओं सम्बन्धी स्थिति सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है [देखिये परिशिष्ट १ अनुबंध संख्या १०) २७ बस्तियों में से ६ बस्तियां ऐसी हैं जिनकी कुछ नियत सेवायें दिल्ली नगर निगम को सौंपनी शेष हैं । इन ६ बस्तियों में से ६ मे सेवायें पूर्ण हो चुकी हैं और निगम से अनुरोध किया है कि उन्हें ले ले । निगम इन को लेने से पहले अपेक्ष्य बिहिताचार को पूर्ण कर रहा है । शेष ३ बस्तियों का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास है और यह सम्भवत: मार्च , १९६२ तक पूर्ण हो जायेगा ।

(घ) तथा (ङ) बस्ती की सेवाओं का प्रबन्ध तथा व्यवस्था स्थानीय निकाय का एक सामान्य कृत्य है । शरणार्थी बस्तियों मे सेवाओं के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व सरकार ने ले लिया था । । प्रत्येक विशेष सेवा कार्य समाप्त होने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग समय समय पर उस सेवा की व्यवस्था का प्रबन्ध निगम को हस्तांतरित करता रहा है । जहां निगम ने किसी सेवा को इस कारण से लेने से इन्कार किया कि वह नगर स्तर से कम है, वह विशेष सेवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षित स्तर पर लाई गयी और निगम को सौंप दी गयी या विशेष निधि निगम को इस प्रयोजन के लिये दी गयी इस बारे में अभी तक निगम को लग भग ३० लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है ।

(च) सड़कें, रास्ते, बरसाती पानी की नलियां, गन्दी नालियां और गलियों की रोशनी का उपबन्ध हो चुका है वे क्षेत्र जिनमें ट्रंक लाइन डाल दी गई है वहां सीवेज तथा पीने के पानी का प्रबन्ध भी कर दिया गया है ।

Quarters in Gole Market Area

67. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether some Government quarters in Gole Market area were declared unfit for human occupation in 1957 and 1958;

(b) if so, whether the very same quarters were re-allotted in 1960 and 1961 without effecting any repairs; and

(c) if so, what is the total loss sustained by Government for keeping these quarters vacant?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chanda): (a) Yes.

(b) Only such quarters as are in a relatively better condition are allotted for temporary use but not for regular occupation.

(c) Until the quarters are in a fit condition for regular allotment, the